Sixteenth Loksabha

>

Title: Need to give reservation to upper caste in government services in Madhya Pradesh.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने 10 प्रतिशत गरीबी के आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने का संविधान संशोधन विधेयक पास किया है। इसकी वजह से पचासों वर्षों से जो सवर्ण युवाओं में आक्रोश की भावना थी, वह समाप्त हुई है, उनमें उत्साह है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से प्रतिबंधित कर दिया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को आदेशित किया जाए कि वह सरकारी नौकरियों में सवर्णों को भी आरक्षण की व्यवस्था करें।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shrimati Riti Pathak are permitted to associate with the issue raised by Shri Janardan Mishra.